

प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 अगस्त, 2019
विषय:-जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में मै० जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लांट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वनभूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ. नं०. 8-07/2019-एफसी, दिनांक 28.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों की गई हैं, जो निम्नवत हैं :-

- The State Government should give details on what action has been taken against unauthorised use of forest land;
- What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in gross violation of Forest (Conservation) Act, 1980;
- Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?
- It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 28.08.2019 में उल्लिखित कर्मियों का निराकरण कर सुस्पष्ट रिपोर्ट/सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

पत्रांक 1191/सी/उ०प्र० शासन, 2019

श्री रामराज बाली, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

श्री मनीष कुमार सिंह, उप सचिव, उ०प्र० लखनऊ

श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

श्री अशोक कुमार

श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ

11403
33
11-9-19

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-472/11-सी-FP/UP/IND/23246/2016, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 04, 2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, भीरजापुर मण्डल, भीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को संस्तुति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- श्री रामराज बाली, अधिकृत प्रतिनिधि, जे०पी० एसोसिएट्स लि०, सेक्टर-128, नोएडा, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

F. No. 8-07/2019-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 1100 03,
Dated: 28th August, 2019

To

The Principal Secretary (Forests)
Department of Environment and Forest
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Sub: Diversion of 115.874 ha. of Forest land in favour of M/S Jai Prakash Associates Ltd. for proposed diversion of forest land at village Kota in Tahsil Robertsganj, district Sonbhadra for JP Super Cement plant & its township (A unit of Jai Prakash Associates Ltd. Sec. 128, Noida) in District Sonbhadra, State Uttar Pradesh.-regarding.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Uttar Pradesh's letter No. 130/14-2-2019-800(162)/2018 dated 25.02.2019 and letter dated 10.06.2019 on the above mentioned subject wherein prior permission of the Central Government under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 is sought. This proposal was been discussed in the meeting held on 06.08.2019 with DDGF (Central), DIGF(Central), Regional Office Lucknow, Nodal Officer (FCA), UP, and User Agency. After the deliberation and discussion in the Ministry the following shortcomings observed:

- i. The State Government should give details on what action has been taken against unauthorised use of forest land;
- ii. What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980;
- iii. Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?
- iv. It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.

In view of the above, the State Government is requested to submit the information, as indicated above, to this Ministry for further consideration of the proposal.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forest (FC)

Copy to:-

1. The PCCF(HoFF), Department of Environment and Forest, Govt. of UP, Lucknow.
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF Department of Environment and Forest, Govt. of UP, Lucknow.
3. The Dy. Inspector General of Forests (Central), Regional Office, Lucknow.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC division.
6. Guard file.